



::प्रधानआयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क::  
O/O THE PRINCIPAL COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE

द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2<sup>nd</sup> Floor, GST Bhavan

रेस कोर्स रिंग रोड / Race Course Ring Road

राजकोट / Rajkot - 360 001

Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142 Email: cexappealsrajkot@gmail.com



सत्यमेव जयते

रजिस्टर्ड डाक ए.डी.द्वारा :-

क	अपील / फाइल नम्बर/ Appeal / File No.	मूल आदेश नं / O.I.O. No.	दिनांक/ Date
	V2/32 /GDM/2018-19	07/AC/Mundra/2017-18	27-03-2018

ख अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.):

**KCH-EXCUS-000-APP-074-2019**

आदेश का दिनांक / Date of Order:	08.07.2019	जारी करने की तारीख / Date of issue:	08.07.2019
------------------------------------	------------	--	------------

श्रीकुमार संतोष, प्रधानआयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /  
Passed by ShriKumar Santosh, Principal Commissioner (Appeals), Rajkot

ग अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर/ वस्तु एवं सेवाकर,  
राजकोट / जामनगर / गांधीधाम। द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सृजित: /  
Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise/ST / GST,  
Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :

घ अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता / Name & Address of the Appellant & Respondent :-

**Saurashtra Infra & Power Pvt. Ltd. Bharat CFS, Zone-I, Adani Port Road, Mundra, Kutch-370421**

इस आदेश (अपील) से ब्याथत काइ ब्याथत निम्नलिखित तरिक म उपयुक्त प्राधिकार / प्राधिकरण क समक्ष अपील दायर कर सकता है।/  
Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

(A) सांभा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलार्थ न्यायाधिकरण क प्रांत अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 का धारा 35B क अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 का धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है।/  
Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

(i) वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर.के. पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए।/  
The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

(ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलों सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, द्वितीय तल, बहुमाली भवन असावा अहमदाबाद- 380015 को की जानी चाहिए।/  
To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2<sup>nd</sup> Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380015 in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above

(iii) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्ट्रार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।/  
The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of duty/demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-

(B) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-5 में चार प्रतियों में की जा सकती एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्ट्रार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।/  
The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and Shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.



- (i) विन अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकती एवं इसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रामाणिक होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। / The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in Form ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.
- (ii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेन्ट्रल) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 के धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपए में अधिक न हो।  
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है  
(i) धारा 11 डी के अंतर्गत रकम  
(ii) सेनवेट जमा की ली गई गलत राशि  
(iii) सेनवेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम  
- बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान विनियम (सं. 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्जी एवं अपील को लागू नहीं होंगे। / For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores, Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include :  
(i) amount determined under Section 11 D;  
(ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;  
(iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules  
- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.
- (C) भारत सरकार कोपनरीक्षण आवेदन :  
**Revision application to Government of India:**  
इस आदेश की पुनरीक्षणयाचिका निम्नलिखित मामला में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथमपरंतुक के अंतर्गत अवर मंचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन इकाई, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। / A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:
- (i) यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहाँ नुकसान किसी माल को किसी कारखाने में भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में। / In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse
- (ii) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छूट (रिवेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। / In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.
- (iii) यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.
- (iv) नृनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए तो इवर्टी क्रेडिट इन अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और रोमे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (नं. 2), 1998 के धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समयावधि पर या बाद में पारित किए गए हैं। / Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.
- (v) उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियाँ प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील)नियमावली, 2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रपण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियाँ संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-3E के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साध्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। / The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-in-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.
- (vi) पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए। / जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रूपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रुपये से ज्यादा हो तो रूपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए। / The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.
- (D) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers various numbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.
- (E) यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-1 के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकिट लगा होना चाहिए। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended.
- (F) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलों को नृनिर्मित करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.
- (G) उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने में संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीनार्थी विभागीय वेबसाइट [www.cbec.gov.in](http://www.cbec.gov.in) को देख सकते हैं। / For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website [www.cbec.gov.in](http://www.cbec.gov.in).



**:: ORDER-IN-APPEAL ::**

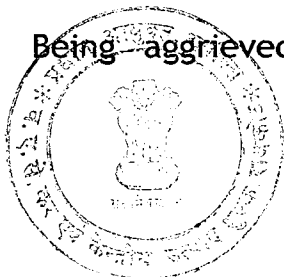
M/s Saurashtra Infra & Power Pvt. Ltd, Bharat CFS Zone 1, Adani Port Road, Mundra, Kutch, Gujarat-370421 having Service Tax Registration No. AAJCS0161NST001(*hereinafter referred to as "Appellant"*) filed Appeal No. V2/32/GDM/2018-19 against Order-in-Original No. 7/AC/Mundra/2017-18 dated 27.03.2018(*hereinafter referred to as 'impugned order'*) passed by the Assistant Commissioner, CGST Division Mundra, Gandhidham Commissionerate (*hereinafter referred to as "lower adjudicating authority"*).

2. The brief facts of the case are that the Appellant was operating Container Freight Station (CFS) at Mundra and provided "Cargo Handling Services", "Storage and Warehousing Services", "Goods Transport Agency Service" and "Business Support Services". During the course of CERA Audit, it was found that Appellant had availed Cenvat credit of certain services during the period from 2011-12 to 2015-16, which were allegedly not qualified as input service in terms of Rule 2(l) of the Cenvat Credit Rules, 2004 (*hereinafter referred to as "CCR,2004"*).

2.2 Show Cause Notice No. V/15-5/Mundra/DSCN/2017-18 dated 6.11.2017 was issued calling upon Appellant to show cause as to why Cenvat credit of Service Tax of Rs. 20,34,019/- should not be disallowed and recovered from them under Rule 14 of CCR,2004 read with Section 73(1) of the Finance Act, 1994 (*hereinafter referred to as "Act"*) along with interest under Rule 14 *ibid* read with Section 75 of the Act and proposing imposition of penalty under Rule 15 of CCR,2004 read with Section 78 of the Act and penalty under Section 77 of the Act.

2.3 The above Show Cause Notice was adjudicated vide the impugned order, which disallowed Cenvat credit of Rs. 20,34,019/- and ordered for its recovery along with interest under Rule 14 of CCR,2004 and also imposed penalty of Rs. 20,34,019/- under Rule 15 of CCR,2004 read with Section 78 of the Act and penalty of Rs. 10,000/- under Section 77 of the Act.

3. ~~Being aggrieved~~ with the impugned order, the Appellant has



सत्यापित,

विपुल शाह  
अधीक्षक (अपील्स)

preferred appeal on the ground that Cenvat credit of Rs. 9,28,649/- as reflected in Annexure-A to the O.O. has been reversed by them on 28.2.2017 on being pointed out by the audit officers and was not being contested by them; that remaining Cenvat credit of Rs. 11,05,370/- is eligible to them as the said services are covered within the definition of 'input service' under Rule 2(i) of CCR, 2004; that these services were used by them in relation to providing of M. S. taxable output services and were not covered under the definition of Rule 2(i) *ibid*, that the impugned order is thus, illegal and voidable.

4. Personal Hearing was held in the case on 18.3.2019, 2.4.2019, 18.4.2019, 5.5.2019 and 4.6.2019. However, neither any response/reply was received from the appellant nor one appeared on their behalf on any of the given five dates or any date thereafter. Hence, I take up the appeal for decision on the basis of available records and the grounds of Appeal as the Appellant has been given sufficient opportunities to represent their case but they failed to do so.

#### Findings:

5. I find that the Appellant has complied with the provisions of Section 35F of the Act by depositing Rs. 20,34,019/- @7.5% of Rs. 20,34,019/- vide Challan No. 00175 dated 11.12.2017 as declared by them in Appeal Memorandum and not demanded by the respondent Gandhidham Commissionerate.

6. I have carefully gone through the facts of the case, the impugned order and grounds of appeal submitted by the appellant in the memorandum of appeal. The issue to be decided is whether the impugned order disallowing Cenvat credit of service tax is correct, legal and proper or not.

7. I find that the Appellant availed Cenvat credit of service tax of Rs. 20,34,019/- during the period from April, 2011 to March, 2016 and the lower adjudicating authority disallowed Cenvat credit on the ground that said services were not covered under the definition of 'input service' in terms of Rule 2(i) of CCR, 2004. The Appellant has not contested

सत्यापित,




विपुल शाह  
अधीक्षक (अपॉल्स)

confirmation of Cenvat credit of Rs. 9,28,649/- as detailed in Annexure-A to SCN but challenged the impugned order so far as it relates to Cenvat credit of Rs. 11,05,370/- detailed in Annexure-B to SCN on the grounds that these services are covered within the definition of 'input service' under Rule 2(l) of CCR, 2004 and these services were used in relation to provision of their taxable output services and not covered under the exclusion clause of Rule 2(l) *ibid*.

7.1 I find that the Appellant has not contested impugned order disallowing Cenvat credit of Rs. 9,28,649/- detailed in Annexure-A of SCN. I, therefore, uphold the impugned order confirming demand of Cenvat credit of Rs. 9,28,649/-, interest at appropriate rate on this amount and penalty of Rs. 9,28,649/- imposed on them under Rule 15 of CCR,2004 read with Section 78 of the Act.

7.2 Regarding confirmation of remaining Cenvat credit of Rs. 11,05,370/- as detailed in Annexure-B of SCN, I find that the impugned order is vague and non-speaking order. The lower adjudicating authority has not spelt out nature of services availed by the Appellant and how the said services are not covered under the definition of input service in terms of Rule 2(l) of CCR, 2004. The Appellant has also given only break up of services in the Appeal Memorandum without giving description of each of the input services availed by them. The Appellant has attached copies of few invoices in Appeal Memorandum but, it is not sufficient to arrive at a decision. Unless, detailed information is available on records, it is not possible to decide admissibility of Cenvat credit. The Appellant did not appear in Personal Hearing despite five opportunities were granted to them. Under the circumstance, availability of Cenvat credit cannot be decided on the basis of records available before me and hence, the matter is required to be remanded to the lower adjudicating authority for passing a reasoned and speaking order.

8. I find that remanding matter to the lower adjudicating authority is legal and proper in light of the decision of the Hon'ble CESTAT in the case of Singh Alloys (P) Ltd. reported as 2012(284) ELT 97 (Tri-Del), wherein it is held that power to remand in appropriate cases is inbuilt in Section

सत्यापित,



विपुल शाह  
अधीक्षक (अपोल्स)

35A(3) of the Central Excise Act, 1944 even after amendment. The Hon'ble CESTAT in the case of M/s. Honda Sell Power Products Ltd. reported as 2013 (257) EIT 361 (Tri-Tal) has also held that Commissioner (Appeals) has inherent power to remand a case under the provisions of Section 35A(3) of the Central Excise Act, 1944. The Hon'ble Gujarat High Court, in Tax Appeal No. 276 of 2014 of Associated Hotels Ltd. has held that even after amendment in Section 35A(3) of the Central Excise Act, 1944 in 2011, the Commissioner (Appeals) has powers to remand.

9. In view of above, I hold that this is a fit case to remand the matter back to the jurisdictional adjudicating authority for de-novo adjudication. The appellant is directed to submit all relevant records and documents in support of their contentions within 30 days from the receipt of this order to the lower adjudicating authority, who shall decide the admissibility of Cenvat credit of service tax of Rs. 11,05,370/- and pass reasoned and speaking order within 3 months from receipt of this order after fair and reasonable opportunities to the Appellant to explain their case.

10. Accordingly, I uphold the impugned order for confirmation of demand, recovery of interest and imposition of penalty for availment of Cenvat credit of Rs. 9,28,649/- but set aside the impugned order for Cenvat credit of Rs. 11,05,370/- and remand the matter back to the lower adjudicating authority to be decided afresh giving the Appellant fair and reasonable opportunity to explain their case.

11. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

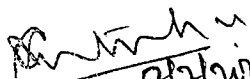
11. The appeal filed by the Appellant is disposed off as above.

सत्यापित,

✓

विपुल शाह

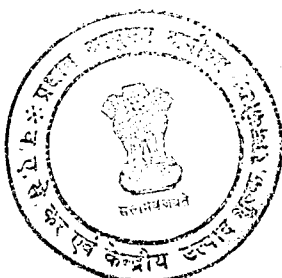
अधीक्षक (अपोल्स)

  
(कुमार संतोष)

प्रधान आयुक्त(अपील्स)

By R.P.A.D.

<p>To, M/s Saurashtra Infra &amp; Power Pvt. Ltd, Bharat CFS Zone 1, Adani Port Road, Mundra, District Kutch.</p>	<p>सेवानें, मे. सौराष्ट्र इन्फ्रा &amp; पावर प्राइवेट लिमिटेड, भारत सीएफएस ज़ोन 1, अदानी पोर्ट रोड, मुँद्रा, जिल्ला कच्छ।</p>
---	---



प्रति :-

- 1) प्रधान मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद को जानकारी हेतु।
- 2) आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कच्छ आयुक्तालय, गांधीधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3) सहायक आयुक्त, सीजीएसटी डिविजन मुँदरा, को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- ✓ 4) गार्ड फ़ाइल।

